Title: Need to amend forest conservation Act as per International standards.

श्री शिशुपाल एन. पाटले (मण्डारा) : उपाध्यक्ष महोद्य, महारा्द्र के विद्र्भ में बहुत अधिक क्षेत्रफल में जंगल हैं, जोकि वन वि्भाग के अधीन हैं। मुख्य रूप से भण्डारा, गोंडिया, गचरौली, चन्द्रपुर एवं नागपुर में ज्यादा तादाद में जंगल हैं। अंतर्राद्रीय मापदंड एवं राट्रीय गणना के अनुसार 33 प्रतिशत जंगल हैं।

ज्बिक इन जिलों में 38 प्रति्शत ्से ज्यादा जंगल व्याप्त है। इतना ही नहीं भारती्य संविधान के परिशिट 5 के अनुसार जो जिले बैक्वर्ड जिलों में आते हैं, उन जिलों के लिए वन संरक्षण कानून शिथिल करने का प्रावधान है।

महारा्द्र के विद्र्भ में बहुत अधिक मात्रा में उच्च कोटि का खनिज उपल्ब्ध है। जि्समें मैंगनीज, ग्रेनाइट जि्सकी अंतर्र्स्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग है। वैसे ही कांच बनाने का कच्चा माल, सोना इत्यादि। इसके उपरांत विद्र्भ में अभी तक वन संख्याण कानून के रूका्वट के कारण कि्सानों के खेती में सिंचाई की सुविधा कुल 11 प्रातिशत है। अगर विद्र्भ के उपरोक्त जिलों को वन संख्याण कानून से छूट दी जाती है, तो 59 प्रतिशत खेती में सिंचाई की सुविधा उपल्ब्ध हो सकेगी। जि्सके कारण विद्र्भ के कि्सान आर्थिक संकट से ऊपर उठेंगे, उच्च कोटि के खनिजों की भारी मात्रा में खानें श्रूक होंगी, जि्स्से विद्र्भ की जनता को एवं बेरोजगार युवकों को रोजगार उपल्ब्ध हो सकेगा। इतना ही नहीं 89 जल विद्युत प्रकल्प वन कानून के कारण प्रलंबित हैं।

में सरकार को सूचित करता हूं और विनती भी करता हूं कि यहां जिलों में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार 33 प्रतिशत से ऊपर वन है एवं भारतीय संविधान के परिशिट 5 के अनुसार उपरोक्त जिले बैक्वर्ड हैं, जो राष्ट्रीय समिवकास योजना में सम्मिलित है, इन जिलों को वन संरक्षण कानून से छूट दी जाए।